RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 090
दि. 29.07.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

'वेंस ने कहा पाक हमले की तैयारी कर रहा, पीएम मोदी बोले- मुंहतोड़ जवाब देंगे...', संसद में जयशंकर ने बताई 9 मई की पूरी कहानी

(एजेंसी)।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच पाकिस्तान को लेकर किसी बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पाकिस्तान द्वारा हमले की चेतावनी दी थी.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में विस्तार से बताया कि भारत-पाकिस्तान टकराव के दौरान चलाए गए 'ऑपरेशन' सिंदूर के दौरान क्या-क्या हुआ था. साथ ही उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने की बात कही थी.

जयशंकर ने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुआ.

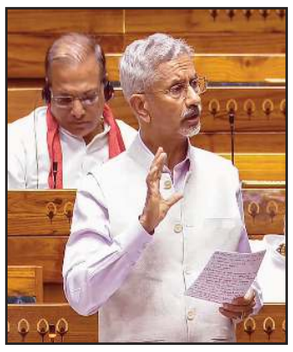

उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था. इस दौरान जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी कर रहे है. जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उससे भी ज्यादा जोरदार जवाब देगा.

जयशंकर ने कहा कि 9 और 10 मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए कई हमलों को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया.

उन्होंने यह भी बताया कि 10 मई को कई देशों ने भारत से संपर्क किया और जानकारी दी कि पाकिस्तान युद्धविराम (सीजफायर) के लिए तैयार है. इस पर भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर युद्धविराम की बात करना चाहता है तो वह केवल सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) के माध्यम से ही बात करे.

विदेश मंत्री जयशंकर संसद के मानसून सत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जवाब देते हुए अमेरिका के साथ हुई बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं था, तो विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष अपने ही विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं करते और दूसरे देश पर भरोसा कर लेते हैं. मुझे आपत्ति है कि उन्हें भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है. मैं जानता हूं कि उनके दल में 'विदेश' शब्द का कितना महत्त्व है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी पार्टी की हर बात संसद पर थोपें. यही वजह है कि वे उस तरफ बैठे हैं और अगले 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे.

गुजरात की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नागरिकों को 'गुजरात@75' डिजाइन की थीम पर आकर्षक 'लोगो' तैयार कर 3 लाख रुपए का पुरस्कार पाने का अमूल्य अवसर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'लोगो' के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नामांकन का ई-प्रारंभ कराया

गांधीनगर, 28 जुलाई : 2035 में गुजरात की स्थापना के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। ऐसे ऐतिहासिक अवसर के उत्सव-समारोह के रूप में गुजरात सरकार ने MyGovindia प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर पर 'लोगो डिजाइन प्रतियोगिता' का आयोजन करने का निर्णय किया है।

इस प्रतियोगिता में गुजरात के 75 वर्ष की इस भव्य यात्रा के प्रतीक के रूप में सृजनात्मक तथा अर्थपूर्ण 'लोगो' आमंत्रित कर, उसके जरिये राज्य के आर्थिक नेतृत्व, टेक्नोलॉजिकल प्रगति, सांस्कृतिक प्रभुता तथा लोक केन्द्रित शासन को उजागर करने का शुभ आशय रहा है।

मुख्यमंत्री ने सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के विशिष्ट अवसर समान इस 'लोगो' डिजाइन की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नामांकन का टट्ळ्प्..ल्ल प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ कराया। देशभर से नागरिक स्वयं द्वारा डिजाइन किए गए 'लोगो' को 28 जुलाई से 14 अगस्त के दौरान सबमिट कर सकेंगे।

इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित 'लोगो' को 3 लाख रुपए का पुरस्कार तथा प्रथम पाँच प्रतियोगियों को मुख्यमंत्री के करकमलों से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

'गुजरात@75 : वाइब्रेंट हेरिटेज, विजनरी फ्यूचर' की थीम के साथ आयोजित होने वाली इस 'गुजरात@75 लोगो प्रतियोगिता' में लोगों की सहभागिता बढ़ाकर तथा लोगों से ही प्राप्त हुए 'लोगो' के जरिये एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर गुजरात की स्थापना के 75 वर्ष के उत्सव में अपनापन सुनिश्चित करने का भाव अभिप्रेत है।

प्रतियोगी गुजरात की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं अद्भुत विरासत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने जो वाइब्रेंट विकास किया है, उसकी अभिव्यक्ति इन 'लोगो' में डिजाइन के जरिये सबमिट कर सकेंगे। प्रतियोगिता के अन्य नियम तथा जानकारी टट्ळ्प्..ल्ल उपलब्ध कराए गए हैं।

यह पहल गुजरात की स्थापना के 75 वर्ष उत्सव को जनभागीदारी से सर्वसमावेशी तथा सर्वव्यापी बनाने का एक नवीन प्रयास है। इतना ही नहीं; इस प्रतियोगिता द्वारा नागरिक गुजरात की विरासत, परंपरा एवं संस्कृति के साथ जुड़ सकेंगे तथा विजेता हुए 'लोगो' 'गुजरात@75' के लिए एक गौरव, विशिष्ट पहचान तथा विशेषता बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने वाराणसी में निमार्णाधीन पर्यटन सुविधा केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज वाराणसी में दुगार्कुण्ड स्थित धर्म संघ शिक्षामण्डल में पर्यटन विभाग द्वारा 05 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से निमार्णाधीन पर्यटन सुविधा केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।

पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य अक्टूबर, 2025 में पूरा कराए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी निरीक्षण के दौरान ने धर्म संघ के मन्दिर में दर्शन-पूजन भी किया तथा गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। इससे पूर्व, धर्म संघ के महंत ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया।

रक्षा मंत्रालय तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा

(एजेंसी)।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 28 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना (डीटीआईएस) के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में, रक्षा मंत्रालय और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

डीटीआईएस 75 प्रतिशत तक सरकारी वित्त पोषण 'अनुदान सहायता' के रूप में प्रदान करता है। शेष 25 प्रतिशत विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य/केन्द्र सरकारें शामिल होती हैं।

यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र परीक्षण सुविधा के लिए, एक निजी संस्था, माइक्रो लैब्स, प्रमुख एसपीवी सदस्य है। एसपीवी संघ के अन्य सदस्य तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और वैधेश्वरन इंडस्ट्रीज हैं। परियोजना के पूरा होने पर, यह सरकारी और निजी दोनों उद्योगों को उन्नत परीक्षण उपकरण और सेवाएं प्रदान करेगा। इससे रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, निजी उद्योग और केंद्र/राज्य सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने हेतु डीटीआईएस का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन के माध्यम से और सैन्य उपकरणों के आयात को कम करके आत्मनिर्भरता

राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा- श्री शिवराज सिंह चौहान

(एजेंसी)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कृषि भवन, नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री शैलेष सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित दोनों केंद्रीय मंत्रालयों और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के तहत 3,286 करोड़ रुपये मजदूरी मद में, 944 करोड़ रुपये मैटिरियल कॉम्पोनेंट में तथा प्रशासनिक मद में 154 करोड़ रुपये यानि कुल 4,384 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान को इसी वित्तीय वर्ष में पिछले दिनों जारी कर दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को राज्य की ओर से धन्यवाद दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण योजना के तहत राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वृहद स्तर पर सर्वे किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि आगे बनने वाले आवासों के सर्वे के सत्यापन का कार्य जैसे ही पूरा हो जाएगा, वैसे ही तुरंत अतिरिक्त मकानों के निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी। राजस्थान में 7.46 लाख मकान बनाए जाने हैं, जिनमें से पीएम-जनमन योजना के तहत भी निर्माण होना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बारे में भी बैठक में चर्चा हुई।

कृषि से जुड़े मुद्दों में 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप', बारिश का पानी संग्रहित करने के लिए तालाब रूपी डिग्गी निर्माण और खेतों में तार की बाड़ लगाने को लेकर योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा हुई। वहीं, जयपुर के बस्सी क्षेत्र में कृषि की उल्लेखनीय प्रगति को लेकर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार की मदद से ग्राम पंचायत स्तर पर 'कृषि पर्यवेक्षकों' की व्यवस्था की मंशा भी जताई।

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनने पर बधाई दी

पीएम मोदी ने दिव्या देशमुख को फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा, "कोनेरू हम्पी ने भी चैंपियनशिप के दौरान जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासोंके लिए शुभकामनाएं।" पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया: दो उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का एक ऐतिहासिक फाइनल! युवा दिव्या देशमुख के 2025 में फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर गर्व है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई, जो कई युवाओं को प्रेरित करेगी।

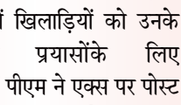

बाढ़ पूवार्नुमान के लिए वेब आधारित सी-फ़्लड प्लेटफॉर्म

केन्द्र सरकार ने एक वेब-आधारित सी-फ्लड प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म गांव स्तर तक दो दिन पहले बाढ़ के बारे में पूवार्नुमान प्रदान करता है, सी-फ्लड वेब-आधारित प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: सी-फ्लड उन्नत 2डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग से प्राप्त बाढ़ के पानी की जानकारी को विस्तार और गहराई की जानकारी के साथ एकीकृत करता है।

इसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से सभी नदी घाटियों के लिए उनकी संबंधित कार्य योजना के अनुसार बाढ़ मॉडलिंग आउटपुट को एकीकृत करने वाली एक एकीकृत बाढ़ सूचना प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है।

प्रारंभिक चरण में यह प्लेटफॉर्म गोदावरी, तापी और महानदी नदी घाटियों के लिए बाढ़ का पूवार्नुमान कवर करता है।

पर्यटन मंत्रालय के इंडियाटूरिज्म दिल्ली ने सांस्कृतिक रंगों के साथ तीज उत्सव का जश्न मनाया

(एजेंसी)।

पर्यटन मंत्रालय के इंडियाटूरिज्म दिल्ली ने 28 जुलाई 2025 को 88, जनपथ, नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय परिसर में बेहद खुशी और उल्लास के साथ तीज महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मेहमानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस दौरान भारतीय परंपराओं, संस्कृति और आतिथ्य का भाव देखने को मिला।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में बड़े स्तर पर मनाई जाने वाली तीज, मानसून के आगमन, साथ ही देवी पार्वती और भगवान शिव के पवित्र पुनर्मिलन का प्रतीक है। यह त्योहार समृद्धि, भक्ति और स्त्रीत्व का प्रतीक है, जिसे पारंपरिक रूप से महिलाएं संगीत, नृत्य, मेहंदी और उत्सव के रीति-रिवाजों के साथ मनाती हैं।

इस कार्यक्रम में कई रंगारंग गतिविधियाँ शामिल थीं, जिनमें शामिल थीं: राजस्थान के पारंपरिक लोक प्रदर्शन, मेहंदी लगाने के बूथ, रंगीन पारंपरिक परिधानों और रंग-बिरंगी चूड़ियों से सजी महिलाएँ

शुद्ध उत्तर भारतीय उत्सवी व्यंजन

तीज की भावना को दशार्ती सुंदर थीम आधारित सजावट, कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को पारंपरिक भारतीय मिठाइयां खिलाई गई, इस कार्यक्रम का खास आकर्षण रही विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी, जिन्होंने इस सांस्कृतिक उत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लिया, मेहंदी के डिजाइन आजमाए, भारतीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। उनकी भागीदारी ने इस उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय रंग भरते हुए इसे जीवंत बना दिया और भारत की जोश-ओ-खरोश से भरी परंपराओं में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी को उजागर किया।

भाषा विश्वविद्यालय में नवीन सत्र हेतु ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा रहीं मुख्य अतिथि

लखनऊ : भाषा विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय में सत्र 2025-26 के B.A.LL.B, LL.B एवं LL.M पाठ्यक्रमों में नवप्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला दिव्यांग पर्वतारोही एवं पद्मश्री सम्मानित डॉ. अरुणिमा सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अपने प्रेरणादायक व्याख्यान में डॉ. सिन्हा ने छात्रों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश दिया। उनके जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को सुनकर छात्रों में आत्मविश्वास व नई ऊर्जा का संचार हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने की। उन्होंने छात्रों को विधि क्षेत्र की विभिन्न संभावनाओं से परिचित कराते हुए विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया।

विभागाध्यक्ष डॉ. पीयूष त्रिवेदी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए छात्रों को अनुशासन, परिश्रम और निरंतर प्रयास के महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर विधि अधिष्ठाता प्रोफेसर मसऊद आलम, कुलसचिव डॉ. महेश कुमार, उप कुलसचिव श्री मोहम्मद साहिल, कुलानुशासक डॉ. नीरज शुक्ला सहित विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकगण एवं अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

ओरिएंटेशन कार्यक्रम में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे अपने करियर की दिशा में मार्गदर्शक बताया।

सम्पादकीय

समस्या को लेकर सराहनीय सुझाव

दिल्ली की मुख्यमंत्री सुश्री रेखा गुप्ता ने पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 वर्ष पुराने वाहनों को ईंधन न देने के प्रादूषण नियंत्रण निकाय के पैसले पर तत्काल रोक तो लगवाई ही साथ ही उन्होंने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस समस्या को लेकर जो सुझाव देने का पैसला किया है, वह न सिर्प तर्वसंगत है बल्कि सराहनीय भी है। मुख्यमंत्री ने अपने सुझाव की जानकारी देते हुए शनिवार को कहा कि यदि उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने का 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाए तो इस अव्यावहारिक आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि के पहले के जो वाहन प्रादूषण पैलाते हैं, वे बच जाएंगे और निर्धारित अवधि के बाद के जो वाहन प्रादूषण नहीं पैलाते क्योंकि उनके अच्छी तरह रखरखाव या कम चलाने के कारण प्रादूषण नहीं फैलाते। वे सड़क से हट जाएंगे। इस अतार्विक एवं अव्यावहारिक अपने 2018 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट वापस ले और सड़क से उन्हीं वाहनों को हटाया जाए जो प्रादूषण फैलाते हों भले ही उनकी उम्र 5 वर्ष ही क्यों न हो। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यदि मुख्यमंत्री गुप्ता का यह सुझाव मान लिया गया तो चालक वाहन की नियमित प्रादूषण सर्टिफिकेट रखने के प्राति सतर्व भी हो जाएंगे। सच में जब राजनेता संवेदनशील तरीके से पैसले लेते हैं तो जनता में उन्हें लोकप्रियता हासिल होती है लेकिन जो लकीर के फकीर होते हैं वे समझदारी से पैसले नहीं ले पाते और उनकी इसी नासमझी का परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बीएसएनएल के प्रदर्शन की समीक्षा की, ग्राहकों की सुविधा और राजस्व सृजन पर जोर दिया

(एजेंसी)।

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में बीएसएनएल की परिचालन प्रगति की समीक्षा की गई, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान किया गया और कंपनी के नेटवर्क एवं सेवा वितरण के लिए आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सत्रों के बीच मीडिया ब्रीफिंग में, श्री सिंधिया ने बताया कि इस बैठक में दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की भूमिका को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

विकास और आधुनिकीकरण पर जोर

समीक्षा के दौरान बीएसएनएल की विकास रणनीति, नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार, ग्राहक सेवा वितरण और संगठनात्मक आधुनिकीकरण पर व्यापक चर्चा हुई। इस व्यापक चर्चा ने बीएसएनएल की एक उपभोक्ता-केंद्रित दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में स्थिति को और मजबूत किया, जिसका स्पष्ट लक्ष्य सभी व्यावसायिक इकाइयों में "राजस्व सर्वोपरि" है। इस मंच ने बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन को हर स्तर पर इन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद की और परिणामों के

लिए जवाबदेही पर जोर दिया।

ग्राहक-प्रथम परिवर्तन

बीएसएनएल अपने सभी सर्किलों, व्यावसायिक क्षेत्रों और इकाइयों में सेवाओं में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अपने "ग्राहक सर्वप्रथम" सिद्धांत को आगे रखने के लिए बीएसएनएल सक्रिय ग्राहक जुड़ाव, बेहतर सेवा जवाबदेही और त्वरित शिकायत निवारण पर जोर दे रहा है।

प्रमुख फोकस क्षेत्र और परिणाम

सीजीएम बैठक के दौरान, बीएसएनएल के सर्किल प्रमुखों को ग्राहक तक पहुंच और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई। पहचाने गए विशेष फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

ग्रामीण, शहरी, उद्यम और खुदरा क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ फिर से जुड़ना

मोबाइल नेटवर्क और फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) में सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में सुधार

बिलिंग, प्रावधान और नेटवर्क अपटाइम में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना

प्रत्येक परिचालन स्तर पर ह्लराजस्व-प्रथमह्व लक्ष्यों के साथ जवाबदेही को बढ़ावा देना

कनेक्टिविटी, वीपीएन समाधान, लीज्ड लाइन सेवाएं और अन्य नए व्यावसायिक अवसरों जैसी उद्यम सेवाओं का विस्तार करना।

श्री सिंधिया ने बीएसएनएल के प्रयासों की सराहना की और ग्राहकों को सुविधा तथा राजस्व सृजन में उल्लेखनीय सुधार लाने के महत्व पर बल दिया।

नई सेवा पहल

समीक्षा के दौरान, बीएसएनएल की हाल ही में शुरू की गई कई नई पहलों पर प्रकाश डाला गया, जिनका उद्देश्य सेवाओं की पेशकश और ग्राहक मूल्य में वृद्धि करना है। इन पहलों में शामिल हैं:

कई दूरसंचार सर्किलों में 4जी का विस्तार और रोलआउट

अगली पीढ़ी के इन्फोटेनमेंट के लिए मोबाइल ग्राहकों के लिए एफटीटीएच और बीआईटीवी प्लेटफॉर्म के लिए आईएफटीवी की शुरूआत

बीएसएनएल राष्ट्रीय वाई-फाई रोमिंग (ग्राहकों के लिए राष्ट्रव्यापी वाई-फाई रोमिंग सेवा)

उद्यम और सरकारी ग्राहकों के लिए अनुकूलित बीएसएनएल वीपीएन सेवाएं और बंडल पैकेज

मिशन-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में उच्च-विश्वसनीयता कनेक्टिविटी के लिए सीएनपीएन परियोजनाएं (निजी नेटवर्क पहल)

स्पैम -मुक्त नेटवर्क - घोटाले और स्पैम संचार को तत्क्षण समाप्त करने के लिए अपनी तरह का पहला समाधान

बीबीए (बीएसएनएल बिजनेस एसोसिएट) के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे शिक्षित युवा बीएसएनएल बिक्री चैनल को मजबूत बनाने और बिक्री कमीशन अर्जित करने में सक्षम होंगे।

डिजिटल रूप से सशक्त भारत की ओर

बीएसएनएल कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अब डिजिटल रूप से सशक्त, सेवा-उन्मुख और वित्तीय रूप से टिकाऊ दूरसंचार ऑपरेटर बनने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। कंपनी पूरे देश में आधुनिक दूरसंचार सेवाओं और बुनियादी ढांचे का विस्तार करके "भारत" को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भागीदारी

(एजेंसी)।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 मई 2025 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 10वीं बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक (सीएमएम) में अपनाई गई घोषणा अनुलग्नक में दी गई है।

ब्रिक्स मंच के अंतर्गत परिकल्पित पहलों का कार्यान्वयन राष्ट्र विशिष्ट है, न कि क्षेत्र विशिष्ट।

ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 10वीं बैठक की घोषणा

प्रस्तावना

हम, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, संघीय गणराज्य ब्राजील की अध्यक्षता में, "अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण देशों के सहयोग को मजबूती" विषय के तहत, हमारे सांस्कृतिक सहयोग एजेंडे में आगे की प्रगति की समीक्षा के लिए 26 मई 2025 को ब्रासीलिया शहर में बैठक की।

ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के अंतर्गत सर्वसम्मति, पारस्परिक सम्मान और समझ, खुलेपन, एकजुटता और संप्रभु समानता की ब्रिक्स भावना का पालन करना;

9 जुलाई 2015 को हस्ताक्षरित संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स देशों की सरकारों के बीच समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को याद करते हुए, और 24 मई 2022 को हस्ताक्षरित समझौते 2022-2026 के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, साथ ही मारोपेंग घोषणा - 2018; क्यूरिटिबा घोषणा - 2019; मॉस्को घोषणा - 2020; नई दिल्ली घोषणा - 2021; बीजिंग घोषणा - 2022; म्पुमलंगा घोषणा - 2023; और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा - 2024;

बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए सहयोग, संवाद और समझ बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए , ब्रिक्स सदस्यों और वैश्विक दक्षिण देशों की सांस्कृतिक विविधता और सतत विकास दृष्टिकोण की बहुलता को स्वीकार करते हुए , जो अधिक टिकाऊ विश्व का पक्षधर है, और वैश्विक शासन में वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण को महत्व देते हुए ;

संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने, विरासत, नवाचार और रचनात्मकता को अत्यधिक महत्व देने, संयुक्त रूप से मजबूत अंतरराष् ट्रीय लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग की वकालत करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान;

रचनात्मकता, नवाचार, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर सतत विकास के प्रमुख प्रवर्तक और चालक के रूप में संस्कृति की शक्ति को मान्यता देना;

समाज के विकास के लिए संस्कृति के आंतरिक मूल्य पर प्रकाश डालना, चुनौतियों का सामना करना और डिजिटल वातावरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों सहित आईसीटी के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न अवसरों पर विचार करना;

सांस्कृतिक संपदा को उनके मूल देशों में वापस लौटाने से समाजों और राज्यों पर पड़ने वाले व्यापक सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, तथा इस संबंध में सभी उपाय करने की नैतिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए, ताकि सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने और अपनी सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच बनाने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का पूर्ण आनंद सुनिश्चित किया जा सके;

इंडोनेशिया को शामिल करने और साझेदार देशों की श्रेणी की स्थापना के माध्यम से ब्रिक्स परिवार के विस्तार

का स्वागत करते हुए, जो वैश्विक दक्षिण को शांति और साझा समृद्धि के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने में सक्षम बनाता है;

9 जुलाई 2015 को ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते को स्वीकार करने के लिए नए ब्रिक्स सदस्यों को प्रोत्साहित करना;

हम निम्नलिखित के माध्यम से अपने सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं:

1. संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था, कॉपीराइट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

1.1 सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों और उद्योगों के बढ़ते आर्थिक भार और आय, सभ्य रोजगार, रचनात्मक कौशल और नवाचार को बढ़ावा देकर समग्र अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देना;

1.2 संस्कृति पर ब्रिक्स कार्य समूह के अंतर्गत सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर एक ब्रिक्स मंच स्थापित करने पर सहमति; तथा सदस्यों, उनकी संबंधित सांस्कृतिक संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं, साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को उसके अधिदेश के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, ब्रिक्स सदस्य देशों की सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन और बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने, सांस्कृतिक सामग्री के प्रसार का विस्तार करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का विकास करने, कलाकारों और सांस्कृतिक व्यवसायियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, साथ ही रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना;

1.3 रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मापने के लिए मान्यता प्राप्त वैश्विक मानकों और संकेतकों के आधार पर ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण, मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय सांख्यिकीय संरचना बनाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना;

1.4 सभी के लिए एक नैतिक, सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी, भरोसेमंद, विकासोन्मुख, न्यायसंगत, पारदर्शी एआई की आवश्यकता की पुष्टि करें, जो राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, लागू अंतरराष्ट्रीय कानून, सम्‍ प्रभुता, मानवाधिकार और सभी महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तिकरण, भाषायी विविधता, सांस्कृतिक विरासत, उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करता हो;

1.5 एआई प्रणालियों के खनन, प्रशिक्षण और विकास में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों द्वारा संरक्षित सामग्री के उपयोग के लिए पारिश्रमिक या लाइसेंस देने पर ब्रिक्स देशों के बीच अनुभव के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर देना;

1.6 डिजिटल वातावरण में एक स्थायी सांस्कृतिक इको-सिस्टम की आवश्यकता की पुष्टि करें जो रचनाकारों, कलाकारों, लेखकों और अन्य अधिकार धारकों को प्रभावी ढंग से समर्थन और उचित पारिश्रमिक प्रदान करे, साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखे, इस प्रकार एक सुलभ, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण डिजिटल वातावरण को सक्षम करे, साथ ही कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा भी करे;

1.7 डिजिटल वातावरण में बहुभाषिकता का समर्थन करना और भाषायी और सांस्कृतिक विविधता को शामिल करने, बढ़ावा देने, सुरक्षा और संरक्षण के लिए बड़े भाषा मॉडल में उपयोग किए जाने वाले सभी एआई मॉडल के प्रशिक्षण डेटासेट की आवश्यकता की पुष्टि करें;

1.8 पुस्तकालयों, अभिलेखीय भण्डारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

2. संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और 2030 के बाद का विकास एजेंडा

2.1 सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर 2022 यूनेस्को विश्व सम्मेलन के अनुरूप, भविष्य के 2030 के बाद के विकास एजेंडे में संस्कृति को एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में शामिल करने के समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं;

2.2. 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी28) में वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए यूएई फ्रेमवर्क के अनुरूप, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता को पहचानना; और जलवायु गतिशीलता के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र की क्षमता पर विचार करना;

2.3 जलवायु प्रयासों में संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखने की वकालत करने में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए संस्कृति-आधारित जलवायु कार्रवाई के मित्रों के समूह (जीएफसीबीसीए) के प्रयासों पर ध्यान दें;

2.4 ब्रिक्स देशों के बीच निम्नलिखित कार्यों के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करनाः () सांस्कृतिक प्रथाओं और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए अनुकूली रणनीति विकसित करके और पारंपरिक ज्ञान, स्वदेशी लोगों के ज्ञान और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों द्वारा निर्देशित जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे को डिजाइन करके जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रभावों से सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण करना; () समाज के सभी स्तरों पर स्थायी प्रथाओं, लचीलेपन और जलवायु-परिवर्तन-संवेदनशील व्यवहार को प्रोत्साहित करने में सांस्कृतिक क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करना;

2.5 यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, हम विकसित देशों से आग्रह करते हैं कि वे विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु वित्त प्रदान करने और जुटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें;

2.6 पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अंतरराष् ट्रीय कानूनी संरक्षण को मजबूत करने का आह्वान करें और डब्ल्यूआईपीओ में चल रही चचाओं पर ध्यान दें।

3. सांस्कृतिक संपदा की वापसी और सुरक्षा

3.1 सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक न्याय, सामंजस्य और सामूहिक स्मृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ पीढ़ियों के बीच ज्ञान प्रसार को मजबूत करने, ऐतिहासिक निरंतरता की रक्षा करने और राज्यों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों में वापस करने के महत्व की पुष्टि करें।

3.2 सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के साथ-साथ विशेष रूप से अपने समुदाय की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत तक पहुंच के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करना।

3.3 सांस्कृतिक संपत्ति को उनके मूल देशों में वापस करने के महत्व को स्वीकार करते हैं और गैर-पदानुक्रमित, सहकारी आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए इसकी क्षमता को स्वीकार करते हैं, और हम इस मामले पर अधिक मजबूत अंतरराष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता को पहचानते हैं।

3.4 अनुभवों, राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, कानून और सफल मामलों को साझा करके, विरासत शिक्षा और संग्रहालय शिक्षा को बढ़ावा देकर, सरकारी उदाहरणों और शैक्षणिक विशेषज्ञों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करके, साथ ही क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुपक्षीय संगठनों में प्राथमिकताओं और नीतियों के बीच तालमेल बिठाकर सांस्कृतिक संपदा की वापसी के विषय में सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होना।

मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम

(एजेंसी)।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए, संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) की स्थापना की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा कार्यान्वित इस मिशन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की इसकी क्षमता का दस्तावेजीकरण करना है।

आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एनएमसीएम ने जून 2023 में मेरा गाँव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) पोर्टल शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना है। वर्तमान में 4.7 लाख गाँव अपने-अपने सांस्कृतिक पोर्टफोलियो के साथ पोर्टल पर लाइव हैं।

एमजीएमडी पोर्टल मौखिक परंपराओं, मान्यताओं, रीति-रिवाजों, ऐतिहासिक महत्व, कला रूपों, पारंपरिक भोजन, प्रमुख कलाकारों, मेलों और त्योहारों, पारंपरिक परिधानों, आभूषणों और स्थानीय स्थलों सहित सांस्कृतिक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। इस पोर्टल में देश में हाशिए पर पड़े समुदायों और देश भर की कम-जानने वाली परंपराओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ भी शामिल हैं।

एनएमसीएम भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांस्कृतिक संपत्तियों का दस्तावेजीकरण और संवर्धन करके, इस मिशन का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना

और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

एमजीएमडी कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए लक्षित गाँवों की कुल संख्या 6.5 लाख है। इसमें पश्चिम बंगाल राज्य के 41,116 गाँव शामिल हैं। अब तक पश्चिम बंगाल के 5,917 गाँवों का मानचित्रण किया जा चुका है और संबंधित डेटा एमजीएमडी वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। शेष 35,199 गाँव दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में हैं।

अभी तक तमिलनाडु सहित राज्यवार उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय सहायता आवंटित/स्वीकृत नहीं की गई है।

वर्तमान में एमजीएमडी वेब पोर्टल पर 4.7 लाख गाँवों का डेटा अपलोड किया जा चुका है। यह डेटा पारंपरिक कला रूपों, अनुष्ठानों और लोक प्रदर्शनों सहित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पहचान और संरक्षण में सहायक होगा।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

सीआईएल ने कोयला खदान अपशिष्ट में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की

(एजेंसी)।

सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) से एकत्रित कोयला-व्युत्पन्न फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश के नमूनों तथा ओवरबर्डन क्ले के नमूनों का सूक्ष्म तत्वों और दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के लिए विश्लेषण किया गया है और परिणाम दशार्ते हैं कि फ्लाई ऐश और क्ले में कुल आरईई लगभग 400 पीपीएम है।

इसके अलावा नेवेली स्थित एनएलसी इंडिया लिमिटेड की खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों से एकत्रित ओवरबर्डन, लिग्नाइट और फ्लाई ऐश के नमूनों का भी दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) और सूक्ष्म तत्वों के लिए विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में पाया गया कि ताप विद्युत संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश में आरईई (2100 मिलीग्राम/किग्रा) की सांद्रता होती है, जिसमें हल्की और भारी दोनों तरह की आरईई और 300 मिलीग्राम/किग्रा यिट्रियम की मात्रा शामिल होती है।

सरकार ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की स्थापना को मंजूरी दी। इस मिशन के अंतर्गत ओवरबर्डन, टेलिंग, फ्लाई ऐश और रेड मड जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति पर केंद्रित पायलट परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएमएम के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना हेतु दिशानिदेर्शों को 6 अप्रैल, 2025 को मंजूरी दे दी गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला खदान अपशिष्ट में पाए जाने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंधित निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाएं शुरू की हैं:

1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) कोयला क्षेत्र से आरईई और अन्य आर्थिक संसाधनों के मूल्यांकन परिणाम बताते हैं कि कुल आरईई कम है, लेकिन भारी आरईई सामग्री अपेक्षाकृत अधिक है।

2. सिंगरौली कोयला क्षेत्र में गोंडवाना तलछट (कोयला, मिट्टी, शेल, बलुआ पत्थर) में सूक्ष्म तत्वों और आरईई सांद्रता के मूल्यांकन दशार्ते हैं

कि आरईई की प्रकृति आशाजनक है (कोयला नमूनों में संपूर्ण कोयला आधार पर लगभग 250 पीपीएम और गैर-कोयला नमूनों में लगभग 400 पीपीएम की समृद्धि के साथ)। हालांकि आरईई का किफायती निष्कर्षण तकनीकी प्रगति और पैमाने की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

3. उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों के ऊपरी स्तरों से आरईई सहित महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, जिसका उद्देश्य () भौतिक पृथक्करण द्वारा गैर-कोयला स्तरों से महत्वपूर्ण धातुओं की संवर्धन तकनीक और () आयन-एक्सचेंज रेजिन द्वारा गैर-कोयला स्तरों और एसिड माइन ड्रेनेज से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण तकनीक को विकसित करना है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), भुवनेश्वर; अलौह सामग्री प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), हैदराबाद और आईआईटी, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

कोयला उत्पादन में वृद्धि

वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन पार कर चुका है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2026-27 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य तैयार किया है।

देश में कोयले की अ धि क ां श आवश्यकता देश में ही कोयला उत्पादन से पूरी होती है। कोयले के आयात में मुख्य रूप से कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के गैर-कोकिंग कोल जैसे आवश्यक आयात शामिल हैं क्योंकि इनका घरेलू उत्पादन, या तो दुर्लभ भंडार या अनुपलब्धता के कारण सीमित है। भविष्य में कोयले की मांग को स्वदेशी स्रोतों से पूरा करने और कोयले के अनावश्यक आयात को कम करने के लिए, अगले कुछ वर्षों में घरेलू कोयला उत्पादन में सालाना 6-7 प्रतिशत की वृद्धि होने और 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

वर्ष 2024-2025 में देशभर में घरेलू कोयला उत्पादन 1047.67 मिलियन टन (अनंतिम) रहा जबकि वर्ष 2023-2024 में यह 997.83 मिलियन टन था। यानी लगभग 4.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 0.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 773.81 मिलियन टन की तुलना में 781.07 मिलियन टन (अनंतिम) कोयला उत्पादन किया।

सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में कोयले के अनावश्यक आयात को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में एकल खिड़की मंजूरी, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 में संशोधन, जिससे कैप्टिव खदानों को अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति मिल सके, एमडीओ मोड के माध्यम से उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों का उपयोग बढ़ाना, नई परियोजनाएं और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार और वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों/सार्वजनिक उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल है। वाणिज्यिक खनन के लिए सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।

(क) कोयला आयात के विकल्प के रूप में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है, खासकर उन मामलों में जहां एसीक्यू को गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए मानक आवश्यकता के 90 प्रतिशत तक घटाया गया था या जहां एसीक्यू को तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए मानक आवश्यकता के 70 प्रतिशत तक घटाया गया था। एसीक्यू बढ़ने से घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

वर्ष 2020 में आरंभ की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में बदलाव द्वारा, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ाने से कोयला आयात में कमी लाने पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

पश्चिम रेलवे द्वारा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया बांद्रा स्टेशन महोत्सव

स्टेशन महोत्सव में भव्य बांद्रा स्टेशन की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक पहचान का जश्न मनाया गया

मुंबई,

बांद्रा स्टेशन की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा एक जीवंत कार्यक्रम "बांद्रा स्टेशन महोत्सव" मनाया गया। 26 जुलाई, 2025 को आयोजित इस भव्य समारोह की शुरूआत पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह, मुंबई क्षेत्र की डाक सेवा की निदेशक श्रीमती कैया अरोड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक विशेष स्मारक कवर के अनावरण के साथ हुई। विशेष कवर का अनावरण एक मार्मिक क्षण था, जो इस प्रतिष्ठित स्टेशन की ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक सच्चा सम्मान था।

(पहली पंक्ति - पहली एवं दूसरी तस्वीरें) पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह, मुंबई क्षेत्र की डाक सेवा की निदेशक श्रीमती कैया अरोड़ा विशेष स्मारक कवर का अनावरण करते हुए। (दूसरी पंक्ति) "आर्ट एंड क्राफ्ट" और "व्लॉग मेकिंग" प्रतियोगिताओं के विजेताओं के साथ गणमान्य व्यक्ति।

बांद्रा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शानदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य प्रदर्शन और ऊर्जावान कराओके प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जिन्होंने उत्सवी माहौल को और भी समृद्ध बना दिया। इस दिन का मुख्य आकर्षण "आर्ट एंड क्राफ्ट" और "व्लॉग मेकिंग" प्रतियोगिताओं के लिए बेसब्री से प्रतीक्षित पुरस्कार वितरण समारोह था। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को उनके कलात्मक और नवोन्मेषी कौशल के साथ-साथ आकर्षक कहानी कहने की कला के लिए सम्मानित किया गया। इन रचनात्मक कृतियों ने बांद्रा स्टेशन की भावना और उसके जीवंत उत्साह को खूबसूरती से दर्शाया।

बांद्रा स्टेशन महोत्सव ने विरासत के उत्सव को सामुदायिक भागीदारी के साथ मिश्रित किया, जिससे इस अवसर की स्थायी यादें बनीं, जो पुरानी यादों, रचनात्मकता और सौहार्द से भरी थीं। जून 2025 में शुरू हुआ यह महोत्सव एक लुभावने समापन के साथ संपन्न हुआ, जब सैकड़ों हीलियम गुब्बारे आकाश में उड़े, जिसने उत्सव की खुशी की भावना को पूरी तरह से दर्शाया।

बांद्रा रेलवे स्टेशन मुंबई के बेहतरीन उपनगरीय रेलवे स्टेशनों में से एक है। अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, यह लाखों दैनिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसे महाराष्ट्र सरकार के 1995 के विरासत नियमों में ग्रेड क विरासत संरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। एक सदी से भी अधिक पुराना रेलवे स्टेशन, यह विक्टोरियन गोथिक और स्थानीय शैली का एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प मिश्रण है, जो अपने स्थल पर एक प्रमुख लैंडमार्क के रूप में उभर कर आता है। बांद्रा स्टेशन 28 नवंबर, 1864 को खोला गया था। हालाँकि, शानदार विरासत बांद्रा स्टेशन भवन 24 साल बाद 1888 में बनाया गया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्थापना दिवस पर भारत की जलवायु तैयारी संबंधी प्रमुख पहल घोषित किए

(एजेंसी)।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जलवायु-अनुकूल और वैज्ञानिक रूप से सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा विकसित नए वैज्ञानिक उपकरण और डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने विज्ञान-संचालित सेवाओं के प्रति गहन जन सहभागिता और व्यापक जागरूकता का आह्वान किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में मंत्रालय के कामकाज, इसकी पहुंच और लोगों के जीवन पर इसके वास्तविक प्रभाव से उल्लेखनीय बदलाव आया है।

डॉ. सिंह ने कहा कि विज्ञान और नवाचार पारिस्थितिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही आगामी दशकों में भारत के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां एक सामान्य उपयोगकर्ता भी अपने मोबाइल फोन पर लाइव मौसम अलर्ट, चक्रवात संबंधी चेतावनी, वायु गुणवत्ता अपडेट और समुद्री पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह मिशन मोड में काम करने वाली सरकार और एक ऐसे मंत्रालय के कार्य परिणाम हैं, जिसने स्वयं को नागरिक सेवा केंद्रित संस्थान के रूप में ढाल लिया है।"

इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित 14 प्रमुख उत्पादों और पहल का औपचारिक शुभारंभ किया। इनमें वर्षा निगरानी और फसल-मौसम कैलेंडर, भारत पूर्वानुमान प्रणाली - विस्तारित अवधि पूर्वानुमान (भारतएफएस-ईआरपी) जैसी उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां, उच्च-रिजॉल्यूशन वर्षा डेटासेट, अद्यतन तरंग एटलस और समुद्र तल चार्ट, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणालियां, समुद्री जैव विविधता रिपोर्ट और चार भारतीय शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण अध्ययन शामिल हैं। इस मौके पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्मित "लाइफ सेविंग इम्पैक्ट" नाम की एक नई डाक्यूमेंटरी (वृत्तचित्र) भी रिलीज की गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछले दस वर्षों में आये व्यापक बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में आज डॉप्लर मौसम रडार की संख्या 15 से बढ़कर 41 हो गई है। इसी तरह, भूकंपीय और मौसम केंद्र, ऊपरी वायु प्रेक्षण प्रणालियां, आकाशीय बिजली

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, सिस्टम का खेल निराला, जिम्मेदारों ने लगाई फर्जी रिपोर्ट

लेखपाल ने आरोपी को ही बनाया गवाह, पुलिस ने शिकायत कर्ता पर की कार्रवाई।

आजमगढ़ : शासन के निर्देशानुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त करना है और भूमि को कब्जे मे लेते हुए वहाँ सरकारी जमीन का बोर्ड लगा देना चाहिए लेकिन राजस्व कर्मचारी इसके विपरीत कार्य करते हुए सुविधा शुल्क लेकर अधिकारियों को भ्रामक रिपोर्ट भेजकर गुमराह करते रहते है। वही इस काम मे पुलिस भी पीछे नही है वहां तो शिकायत कर्ता पर ही कार्यवाही करते हुए भ्रामक रिपोर्ट लगा अपने आका को गुमराह करते है। शासन प्रशासन इन नीचे के कर्मचारियों का कटपुतली बनकर रह जता है।

ताजा मामला ग्राम बस्ती भुजबल परगना कौड़िया तहसील बूढ़नपुर आजमगढ़ का है।

बताते चले कि बीते जून माह की 13 तारिख को ग्राम बस्ती भुजबल, परगना कौड़ियां, तहसील बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ में गाटा संख्या 161 रकबा 0.024 हे० की नवीन परती/सरकारी भूमि पर नीरज गुप्ता ऊर्फ नीरज मोदनवाल पुत्र दिनेश मोदनवाल और दिनेश मोदनवाल, योगेन्द्र यादव ऊर्फ बाबूलाल यादव अपने सहयोगियों के साथ राजस्व कर्मियों एव पुलिस की मिलीभगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिसकी सूचना जागरूक नागरिक अंसल ने एन्टी भू माफिया पर शिकायत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से किया था जिसकी जांच क्रम लेखपाल कानूनगो ने आरोपी को ही गवाह बनाते हुए नवीन परती पर कोई कब्जा न होने और नहर की पटरी की फोटो लगाकर रिपोर्ट लगा दिया।

वहीं सी ओ बूढ़नपुर ने घटना के दिन की फोटो लगाकर काम रुकवाने और कोई कब्जा न होने की रिपोर्ट लगाया है। जबकि मौके पर दिवाल उठाकर कब्जा किया गया है।

कानून गो ने धमकाया,पुलिस ने की शांति भंग में की कार्रवाई।

राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगाने पर शिकायत कर्ता ने पुनः मुख्मयंत्री पोर्टल पर शिकायत किया तो बौखलाए राजस्व निरीक्षक ने शिकायत कर्ता से काल कर अभद्रता भाषा का प्रयोग किया।

वहीं स्थानीय पुलिस थाना अहरौला ने शिकायत कर्ता के पिता पर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। शिकायत कर्ता के पिता लखनऊ मे रहते है।

शिकायत कर्ता के पिता दयाशंकर चौबे ने आजमगढ़ के राजस्व कर्मचारी एवं पुलिस की भ्रामक रिपोर्ट लगाने

भारत रेलवे उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनता जा रहा है

माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात के वडोदरा के सावली स्थित एल्सटॉम कारखाने का दौरा किया।

मंत्री महोदय के साथ वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी, सावली के विधायक श्री केतन इनामदार, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, वडोदरा और अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे।

नमो भारत कोचों का उत्पादनः एल्सटॉम कारखाने में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेल मंत्री को कारखाने में चल रहे विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी।

मंत्री महोदय ने अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित 'नमो भारत' कोचों के आधुनिक डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता की सराहना की।

(रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और वडोदरा के सांसद डॉ. हेमांग जोशी, सावली कारखाने में निर्मित 'नमो भारत' कोचों के संबंध में एल्सटॉम के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए)

समग्र रखरखाव गतिविधियाँः

एल्स्टॉम टीम ने मंत्री को रखरखाव गतिविधियों, जिनमें सामग्री का उपयोग और आपूर्तिकर्ता एकीकरण शामिल है, के बारे में जानकारी दी। चचाओं में सेंसर और एआई का उपयोग करके निवारक रखरखाव भी शामिल था।

मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड

रेल मंत्री को कंपनी के हर ऑर्डर के साथ उपकरणों के डिजाइन को निरंतर उन्नत करने के अभिनव दृष्टिकोण से अवगत कराया गया। मंत्री ने एल्स्टॉम को उसके 'डिजाइन इन इंडिया' रेलवे उपकरणों के लिए बधाई दी।

कारखाने में निर्मित कोच, लोकोमोटिव, बोगियां, प्रणोदन प्रणालियाँ आदि दुनिया भर में निर्यात की जाती हैं। ये रेलवे उपकरण 'डिजाइन, डेवलप, डिलीवर फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड इनिशिएटिव' के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको और अन्य देशों तक पहुँच रहे हैं।

"भारत में रेलवे निर्माण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विजन का प्रभाव देख रहा है। भारत अब दुनिया के कई विकसित देशों को रेलवे के कलपुर्जे, कोच और लोकोमोटिव निर्यात कर रहा है", मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता पर रेल मंत्री ने कहा।

सावली कारखाने ने वडोदरा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का सृजन किया है और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान दिया है।

भारत में प्रतिभा विकास, विश्व के लिए

मंत्री को भारत में एल्सटॉम द्वारा की जा रही प्रतिभा विकास गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत में एल्सटॉम के लगभग 7,000 इंजीनियर हैं, जिनमें रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग सिस्टम दोनों शामिल हैं। इनमें से लगभग 300 इंजीनियर अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्यरत हैं।

मंत्री ने एल्सटॉम के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रुचि व्यक्त की और गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ सहयोग का सुझाव दिया। उन्होंने एल्सटॉम, सावली और पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के बीच मौजूदा प्रशिक्षण साझेदारी की सराहना की।

मंत्री ने एल्सटॉम टीम से भारतीय रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर ऑफ-कैंपस और ऑन-साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और उनकी टीमों को इन कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य पाकिस्तान को उसके छद्म युद्ध के लिए दंडित करना था : रक्षा मंत्री

(एजेंसी)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई, 2025 को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पार करना या शत्रु क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान द्वारा वर्षों से पोषित आतंकी ढांचे को नष्ट करना और सीमा पार से किये गये हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले निर्दोष परिवारों को न्याय दिलाना था। श्री सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अचानक आवेश से भरा पागलपन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति और पुरानी कुंठा बताया और इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का समग्र राजनीतिक-सैन्य उद्देश्य आतंकवाद के छद्म युद्ध लड़ने वाले पाकिस्तान को दंडित करना था।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता, बल्कि अपने राष्ट्रीय संकल्प, नैतिक बल और राजनीतिक कौशल का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी आतंकवादी हमले का निर्णायक और स्पष्ट जवाब देगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह और समर्थन देने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेलिंग या अन्य दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को, अमानवीयता का सबसे घिनौना उदाहरण बताया, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर मार डाला गया। यह भारत की सहनशीलता की परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि हमले के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को विवेक, रणनीतिक समझ और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया, जो सिर्फ. एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, अस्मिता और देश के लोगों के प्रति सरकार के दायित्व और आतंकवाद के विरुद्ध उसकी प्रभावी नीति का

निर्णायक प्रदर्शन था।

उन्होंने कहा कि हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल परिपक्वता दिखाई, बल्कि वैसी रणनीतिक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की, जिसकी भारत जैसी ज़िम्मेदार शक्ति से अपेक्षा की जाती है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कई विकल्प मौजूद थे, लेकिन हमने वह विकल्प चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों का अधिकतम नुकसान हो, पर आम पाकिस्तानी नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। उन्होंने कहा कि अनुमान के अनुसार हमारे बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ढांचों पर किए गए सुनियोजित हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, आका और सहयोगी मारे गए। अधिकतर आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े थे, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का खुला समर्थन मिला हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा में की गई, यह न तो उकसावे वाली थी और न ही विस्तारवादी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 मई, 2025 को पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलों, ड्रोनों, रॉकेटों और लंबी दूरी के अन्य हथियारों से हमले किये, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का भी व्यापक इस्तेमाल किया और भारतीय वायुसेना के ठिकानों, भारतीय सेना के गोला-बारूद डिपो, हवाई अड्डों और सैन्य छावनियों को निशाना बनाने की कोशिश की।

एमएसएमई के लिए नया डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल उसके ऋण अनुमोदन को तेज करने के लिए वास्तविक समय के डिजिटल डेटा का लाभ उठाता है

(एजेंसी)।

केंद्रीय बजट 2024-25 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के लिए नए डिजिटल ऋण मूल्यांकन मॉडल की घोषणा की गई थी। इस मॉडल में यह परिकल्पना की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स के स्कोरिंग के आधार पर एक नया

ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने 6 मार्च, 2025 को एमएसएमई के लिए नए ऋण मूल्यांकन मॉडल का शुभारंभ किया था।

यह मॉडल डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का लाभ उठाता है और सभी ऋण आवेदनों के लिए वस्तुनिष्ठ निर्णय और बैंक के लिए मौजूदा (ईटीबी) और बैंक के लिए नए (एनटीबी) एमएसएमई उधारकताओं दोनों के लिए मॉडल-आधारित सीमा मूल्यांकन का उपयोग करके एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित यात्रा तैयार करता है।

इस मॉडल में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल फुटप्रिंट में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का इस्तेमाल करके पैन प्रमाणीकरण, ओटीपी का इस्तेमाल करके मोबाइल और ईमेल सत्यापन, सेवा प्रदाताओं के जरिए ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) से जीएसटी डेटा प्राप्त करना, अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करके बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईटीआर अपलोड और सत्यापन, एपीआई सक्षम वाणिज्यिक और उपभोक्ता ब्यूरो प्राप्त करना और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) का इस्तेमाल करके उचित परिश्रम, एपीआई के जरिए धोखाधड़ी की जांच आदि शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल अलग-अलग ऋण राशि की सीमा वाले सभी बैंकों पर लागू होगा।

पारंपरिक/मैन्युअल पद्धतियों के अंतर्गत बैंक मैन्युअल अंडरराइटिंग के लिए ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत भौतिक दस्तावेजों पर निर्भर रहते हैं, जबकि नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के अंतर्गत क्रेडिट अनुरोध और डेटा प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ मूल्यांकन पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

वडनगर सिटी के समीप रेलवे अंडरपास संख्या 41ए, 30 सितंबर तक बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के महेसाणा-तारंगा रेलखंड पर वडनगर सिटी के समीप स्थित रेलवे अंडरपास (फ्वइ) संख्या 41अ (केसीम्पा खेतों का मार्ग विस्तार) को मानसून के दौरान 30 सितंबर तक आमजन के लिए बंद कर दिया गया है।

भारी वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा और रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जनहित एवं सुचारु तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

विसनगर के समीप रेलवे अंडरपास 16 डी एवं 22ए, 30 सितंबर तक बंद रहेगा

अहमदाबाद मंडल के महेसाणा-तारंगा रेलखंड पर स्थित रेलवे अंडरपास (फ्वइ) संख्या 16ऊ (शेरडीनगर से कांसा विस्तार मार्ग) एवं फ्वइ संख्या 22अ (मस्तान नगर सोसायटी, वडनगर दरवाजा) को मानसून के दौरान 30 सितंबर 2025 तक आमजन के लिए बंद किया गया है।

भारी वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को देखते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा और रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जनहित एवं सुचारु तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया

(एजेंसी)।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया।

इस अवसर पर भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकी भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिजवी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सीपीएसई के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक, स्वायत्त निकायों और मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न उद्योग संघों एवं परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस मौके पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरासत और योगदान को श्रद्धांजलि स्वरूप एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें की को एक दृश्य दी गई। यह फिल्म उनके जीवन की दुर्लभ झलकियों और प्रभावशाली वर्णन के माध्यम से उन्हें एक राष्ट्र निमार्ता और दूरदर्शी नेता के रूप में

प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से भारत के औद्योगिक विकास की नीव रखने में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है।

अपने संबोधन में मंत्री महोदय ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में और बाद में केंद्रीय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में डॉ. मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री वर्मा ने देश के औद्योगिक और संस्थागत विकास में डॉ. मुखर्जी के मूलभूत योगदान को भी रेखांकित किया और उन्हें एक प्रखर विद्वान, राजनेता, निर्भिक सांसद और शिक्षाविद् के रूप में याद किया - जिनका जीवन साहस, दृढ़ विश्वास और "एक राष्ट्र, एक संविधान" में अटूट विश्वास का एक कालातीत प्रतीक बना हुआ है।

उद्घाटन भाषण देते हुए भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री कामरान रिजवी ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए डॉ. मुखर्जी के विजन पर बल दिया, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर उनके जोर को रेखांकित किया।

इस अवसर पर आमंत्रित वक्ता श्री बिनय कुमार सिंह, जो डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक है, ने डॉ. मुखर्जी के जीवन और विरासत पर एक विचारोत्तेजक व्याख्यान दिया। उनके सम्बोधन ने डॉ. मुखर्जी के मूल्यों, विजन और बहुआयामी योगदान की गहरी समझ प्रदान की और भावी पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा।

पीएम-जनमन के कार्यान्वयन में जुलाई 2025 के लिए गुजरात देश में अव्वल

पीएम-जनमन के अंतर्गत गुजरात में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12,489 आवास स्वीकृत किए गए

पीएम-जनमन के अंतर्गत विशेष विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के 5200 घरों में बिजली पहुंचाई गई, 37 मोबाइल टावर लगाए गए

पीएम-जनमन योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतर को दूर कर पीजीवीटी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है

गांधीनगर, 28 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की आवश्यक जरूरतों और सुविधाओं की पूर्ति कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) मिशन के कार्यान्वयन में गुजरात जुलाई 2025 के लिए देश भर में अव्वल राज्य बना है। पीएम जनमन योजना के कार्यान्वयन के लिए हर महीने जारी की जाने वाली स्टेट रैंकिंग के तहत जुलाई महीने में गुजरात पहले स्थान पर रहा है। यह बताता है कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर, 2023 को 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर देश के 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) मिशन की शुरूआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य निश्चित समयसीमा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, आजीविका और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है।

शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान एनईपी 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का शुभारंभ करेंगे

(एजेंसी)।

शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई, 2025 को भारत मंडपम परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 2025 का आयोजन कर रहा है । दिन भर चलने वाले इस विचार-विमर्श का उद्घाटन शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) 2025, शिक्षाविदों, नीति निमार्ताओं, शिक्षकों, उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर वे एनईपी 2020 के तहत हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा करके आगे का रास्ता निर्धारित करेंगे। एबीएसएस 2025 के दौरान होने वाले विचार-विमर्श में शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यावहारिक, कौशल-उन्मुख और रोजगार के अवसरों के साथ समेकित रूप से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र एक सशक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हों। चर्चा में विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा को 2030 तक शत-प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने हेतु पुनर्परिभाषित करने, भारतीय भाषाओं, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को मुख्यधारा में लाने और सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु समावेशिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्र. एबीएसएस 2025: एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ

अपनी शुरूआत के बाद से पिछले पांच वर्षों में, एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में भारत के शिक्षा परिदृश्य में क्रांति ला दी है, और ऐसी परिवर्तनकारी नीतियां पेश की हैं जो अनुकूलन, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से शैक्षणिक, कौशल-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा में निर्बाध ऋण वितरण को सक्षम बनाया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ने 2,469 संस्थानों को शामिल किया है और 32 करोड़ से ज्यादा पहचान पत्र जारी किए हैं, जिनमें से 2.36 करोड़ विशिष्ट अपार (एपीएएआर) पहचान पत्र पहले ही क्रेडिट के साथ सीडेड हैं। 153 विश्वविद्यालयों में बहु-प्रवेश और निकास विकल्पों की शुरूआत, जबकि यूजीसी द्वारा अनुमोदित द्विवार्षिक प्रवेश, भारत को 2035 तक अपने 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, 116 उच्च शिक्षा संस्थान 1,149 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, जिससे 19 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष पूरे होने पर समापन समारोह आयोजित

श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री बळवंतसिंह राजपूत की प्रेरक उपस्थिति

जिस देश में त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना हो, उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 28 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की स्थापना के स्वर्णिम 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समापन समारोह में कहा कि जिस देश में त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना होती है, उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता। भारतीय मजदूर संघ इसी मंत्र को लेकर अविरत कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में सोमवार को गांधीनगर में भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष पूरे होने के जश्न का समापन समारोह श्रम श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री बळवंतसिंह राजपूत की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 'हर हाथ को काम और हर काम का सम्मान' यानी हर काम को सम्मान मिलना चाहिए। हर किसी को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए।

श्रमिकों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से श्रमिकों को केवल पांच रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी अन्नपूर्णा केंद्रों पर अधिक से अधिक श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन का लाभ मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश के नागरिकों को उनके घर की चौखट पर ही विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल रहा है। सामान्य, अदने-गरीब लोगों को पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं सौ फीसदी पहुंचाई जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार पर नागरिकों का विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत@2047' का संकल्प किया है।

जीएचटीसी-इंडिया के तहत देश में लाइट हाउस की स्थिति

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत, निर्माण क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा नवीन, टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-रोधी तकनीकों और निर्माण सामग्रियों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की गई है, ताकि पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) सहित पूरे देश में घरों का तेज, लागत-प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जा सके। वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती- भारत (जीएचटीसी-इंडिया) की शुरूआत, पूर्वनिर्मित तकनीक सहित विश्व स्तर पर उपलब्ध बेहतरीन निर्माण तकनीकों की पहचान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए की गई थी, जिससे तेज, सतत, हरित और आपदा-रोधी निर्माण हो सकें। जीएचटीसी-इंडिया के तहत, दुनिया भर से 54 नवीनता प्रमाणित निर्माण तकनीकों का चयन किया गया था।

जीएचटीसी-इंडिया के तहत 54 चिन्हित प्रौद्योगिकियों में से, 1,000 से अधिक घरों वाली छह लाइट हाउस परियोजनाएं (एलएचपी), जिनमें छह अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी ढांचा सुविधाएं तैयार की गईं हैं, उनका निर्माण इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), रांची (झारखंड), अगरतला (त्रिपुरा) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 843.59 करोड़ रुपये है। देश में मुख्यधारा में लाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को दर्शाने हेतु, एलएचपी की साइटों को, चुनौती प्रक्रिया के जरिए चुना गया था। चेन्नई, राजकोट, इंदौर, लखनऊ और रांची में एलएचपी का निर्माण पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया है। अगरतला में एलएचपी का निर्माण तेजी से जारी है। शहरी योजनाकारों, बिल्डरों और अन्य हितधारकों के बीच नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों/ प्रणालियों के उपयोग और भारत के संदर्भ में इन तकनीकों को मुख्यधारा में लाने के बारे में व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एलएचपी ने लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में काम किया है।

यह जानकारी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

कौशल विकास के माध्यम से स्टार्टअप को समर्थन

(एजेंसी)।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एस.आई.एम.) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल और उच्च-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) शामिल हैं। इसे देश भर के सभी समाजिक वर्गों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हों तथा इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करता है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाली संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जिनका कार्य संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है। एनएसडीसी, बाजार-आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत, उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग जगत की माँग के साथ सहयोग और कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करते हैं।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नए युग/भविष्य के कौशल वाली नौकरी-भूमिकाओं को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) डीजीटी ने 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियाँ आधुनिक तकनीकों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कदम

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई, 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर 2019 में हासिल किया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्ज्वला 2.0 को अगस्त 2021 में 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। यह लक्ष्य भी जनवरी 2022 में हासिल किया गया। इसके बाद, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया और दिसंबर 2022 के दौरान 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी जिसे जुलाई 2024 तक हासिल कर लिया गया।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की निगरानी पीपीएसी की खपत रिपोर्ट, कॉमन एलपीजी डेटा प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) और ओएमसी के साथ बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि भोजन की आदतें, परिवार का आकार, खाना बनाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, कीमत, वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने और एलपीजी उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए, ओएमसी नियमित रूप से ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायत आयोजित करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें सब्सिडी राशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद खर्च को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम की जगह 5 किलोग्राम सिलेंडर का विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए मनाने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन व जागरूकता अभियान शामिल हैं।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक) के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी के बाद, भारत सरकार दिल्ली में 553 रुपये प्रति सिलेंडर की प्रभावी कीमत पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर 4.47 (वित्त वर्ष 2024-25) हो गई है।

पीएमयूवाई कनेक्शनों की निष्क्रियता का आकलन उन उपभोक्ताओं के माध्यम से किया जा सकता है जिन्होंने कनेक्शन लगवाने के बाद कोई रिफि ल नहीं लिया है।

तटीय क्षेत्रों के लिए जलवायु प्रतिरोधी विद्युत अवसंरचना

(एजेंसी)।

विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, विद्युत वितरण एक लाइसेंसी गतिविधि है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल, सुरक्षित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे और बनाए रखे।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार हेतु पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के तटीय क्षेत्रों के लिए 3,088 करोड़ रुपये की लागत के आपदा/चक्रवात रोधी कार्यों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्यों में एचटी और एलटी भूमिगत केबलिंग, रिंग मेन यूनिट (आरएमयू), एरियल बंच्ड केबलिंग (एबीसी), वितरण ट्रांसफार्मरों का विस्तार आदि शामिल हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना, ग्रिड सुदृढ़ीकरण, आपदा प्रतिरोधी उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क पर केंद्रित है, ताकि मौसम के अति संबंधी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए कोंकण क्षेत्र जैसे तटीय क्षेत्रों सहित सभी भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2022 और सीईए (ग्रिड मानक) विनियम 2010 में तटीय क्षेत्रों में भूमिगत केबलों के उपयोग, आउटेज को न्यूनतम करने के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली, भूकंप संभावित क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों में जीआईएस सबस्टेशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित 'तटीय क्षेत्रों में चक्रवात प्रतिरोधी मजबूत विद्युत पारेषण और वितरण अवसंरचना' पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट जून 2021 में सभी हितधारकों को वितरित की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा के 20 से 30 किमी के भीतर चक्रवात संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर सकते हैं और इन क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली का कोई भी नया निर्माण/पुनर्निर्माण रिपोर्ट में निर्धारित डिजाइन मापदंडों का पालन करेगा।

महाराष्ट्र राज्य के लिए, आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 17,237 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें स्मार्ट ग्रिड के लिए आवश्यक सबस्टेशन, भूमिगत केबलिंग, नेटवर्क का विस्तार आदि शामिल हैं। स्वीकृत कार्यों में निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं: मुंबई शहर के लिए 144 करोड़ रुपये की लागत से एससीऐडीऐ (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) और डीएमएस (वितरण प्रबंधन प्रणाली) का कार्यान्वयन।

आईटी/ओटी कार्य जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान, बिलिंग सॉफ्टवेयर, लोड पूवार्नुमान और संबंधित उपकरण और बेस्ट तथा एमएसईडीसीएल डिस्कॉम के लिए 244 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य आईटी मॉड्यूल।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के तहत 2.35 करोड़ उपभोक्ता मीटर, 4.1 लाख वितरण ट्रांसफार्मर मीटर और 29,214 फीडर मीटर के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं।

हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) की प्रगति

(एजेंसी)।

भारत सरकार ने हाइड्रो पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसेः-

सक्षम अवसंरचना जैसे सड़कें, पुल, रोपवे, रेलवे साइडिंग, संचार अवसंरचना और विद्युत गृह से निकटतम पूलिंग बिंदु तक ट्रांसमिशन लाइन, की लागत के लिए बजटीय सहायता, जिसमें राज्य या केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के पूलिंग सबस्टेशनों का उन्नयन शामिल है।

अप्रैल, 2023 में विद्युत मंत्रालय ने पीएसपी के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश पीएसपी स्थलों के आवंटन, मुफ्त बिजली दायित्व/स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से छूट, पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने और समाप्त हो चुकी कोयला खदानों के उपयोग आदि के विभिन्न तरीकों का प्रावधान करते हैं।

जिन पीएसपी के लिए निर्माण कार्य 30.06.2028 को या उससे पहले दिया गया है, उनका अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क माफ किया जाएगा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और उसकी सहमति के लिए संशोधित दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। संशोधित दिशानिदेर्शों के तहत, सभी प्रकार की पीएसपी के लिए डीपीआर की सहमति की समय-सीमा 90 दिनों से घटाकर 50 दिन कर दी गई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) और जल विद्युत परियोजनाओं (पीएसपी) की सर्वेक्षण एवं जांच (एस एंड आई) गतिविधियों की निगरानी के लिए "जल विद्युत डीपीआर" पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल मूल्यांकन एजेंसियों और डेवलपर्स के कार्यप्रवाह और लंबित कार्यों का वास्तविक समय पर ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाता है, जिससे देरी की पहचान और समाधान करने में मदद मिलती है।

विभिन्न हितधारकों के बीच उचित जोखिम-साझाकरण के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद ढांचा प्रदान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने पंप भंडारण संयंत्रों से भंडारण क्षमता/संग्रहीत ऊर्जा की खरीद के लिए टीबीसीबी दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने 18.05.2023 को कुछ शर्तों के अधीन बी2 श्रेणी के तहत पीएसपी का मूल्यांकन करने की अधिसूचना जारी की है।

14.08.2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऑफ स्टीम पीएसपी से संबंधित प्रस्तावों के लिए विशिष्ट टीओआर जारी किया, जिसमें ऑफ स्टीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक सीजन (मानसून के अलावा) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह निर्धारित किया गया है और ऑफ स्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए दो सीजन (मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह निर्धारित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगस्त 2024 में वन क्षेत्र में ड्रिलिंग जांच के प्रावधानों को खनन गतिविधियों के समान पीएसपी तक विस्तारित करने की अनुमति दी है।

30.06.2025 तक हाइड्रो पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की स्थिति निम्नानुसार है:

6.2 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 10 पीएसपी चालू किए गए हैं।

कुल 8.5 गीगावाट क्षमता वाले 8 पीएसपी निमार्णाधीन हैं।

सीईए द्वारा 5.8 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 5 पीएसपी को मंजूरी दी गई है।

64.8 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 46 पीएसपी डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन हैं।

यह जानकारी विद्युत राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एमएनआरई ने सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम आदेश में संशोधन जारी

(एजेंसी)।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने पहले 10.04.2021 से सौर पीवी मॉड्यूल के लिए मॉडल और निमार्ताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) और 01.06.2026 से सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएम को अधिसूचित किया था।

एएलएमएम उत्पादकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और साथ ही देश की व्यापक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था ने देश में घरेलू सौर विनिर्माण उद्योग को तेजी से बढ़ावा देने में भी मदद की है, जो वर्तमान में 91 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल और 27 गीगावाट सौर पीवी सेल क्षमता पर है।

सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम पर दिनांक 09.12.2024 के आदेश में संशोधन दिनांक 28.07.2025 को जारी किया गया है, ताकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा बोली लगाई जाने वाली परियोजनाओं की प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट और सरल बनाया जा सके। संशोधित प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम, सौर पीवी सेलों के लिए एएलएमएम सूची के प्रकाशन के एक महीने बाद ही अनिवार्य होगा, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। हालाँकि, 1 जून 2026 के बाद चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए एएलएमएम सूची के तहत सौर पीवी सेलों के अनिवार्य उपयोग की प्रभावी तिथि, पूर्व अधिसूचित तिथि के अनुसार ही रहेगी।